पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 19, अंक 1/2018

ई-कॉमर्स पर रेगुलेटर होना जरूरी

50 प्रतिशत से ज्यादा उपभोक्ता ऑनलाइन खरीददारी करते समय परेशानी महसूस करते हैं। इसकी मुख्य वजह इंटरनेट का धीमा होना और भुगतान का पूरा नहीं हो पाना है। यही नहीं 56 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ऑनलाइन खरीदे गए सामान की गुणवत्ता में भी कमी पाई। इन समस्याओं के निदान के लिए ऑनलाइन खरीददारी पर एक रेगुलेटर होना आवश्यक है। यह कहना है 'कट्स' के महामंत्री प्रदीप महता का।

'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' के अवसर पर 'कट्स' द्वारा जयपुर में आयोजित 'स्वस्थ एवं न्यायोचित डिजिटल बाजार व्यवस्था को सुनिश्चित करना' विषयक कार्यक्रम में उन्होंने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस दिन दुनियाभर के उपभोक्ता आंदोलनकारी उपभोक्ता अधिकारों पर एकजुट होकर काम करते हैं। यह दिवस अन्तरर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता शक्ति का परिचायक है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार भी ई-कॉमर्स पॉलिसी पर काम कर रही है।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए मुग्धा सिन्हा, सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग, राजस्थान सरकार ने कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में अवगत कराने की आवश्यकता है। एक निष्पक्ष और सक्षम रेगुलेटर ही आम जनता के हित में काम कर सकता है। उपभोक्ताओं को अपने डेटा की सुरक्षा के प्रति ज्यादा सजग रहना होगा।

कार्यक्रम के प्रारंभ में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने अपने स्वागत उद्बोधन में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की विषय वस्तु के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ई-कॉमर्स के युग में उपभोक्ताओं को ऑनलाइन खरीददारी करने एवं सेवाएं लेने में सावधानी रखना आवश्यक है।

विशिष्ट अतिथि मनीष लोढ़ा, संयुक्त निदेशक, ट्राई ने बताया कि ट्राई ई-कॉमर्स को रेगुलेट करता है और इस क्षेत्र में आने वाली विभिन्न बाधाओं को हटाता है। कार्यक्रम में 70 से भी ज्यादा उपभोक्ता संस्थाओं के प्रतिनिधियों, मीडिया एवं गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया।

सर्वेक्षण में यह भी आया सामने

ऑनलाइन शॉपिंग और ई-बाजार पर हाल ही 'कट्स' द्वारा जयपुर के शिक्षित युवा वर्ग में कराए गए एक सर्वेक्षण में करीब 70 फीसदी ने जहां ऑनलाइन खरीददारी को सुरक्षित माना वहीं 56 फीसदी लोगों को खरीददारी के बाद कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। औसतन 48 फीसदी लोग महीने में एक बार और 20 फीसदी लोग सप्ताह में एक बार ऑनलाइन वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करते हैं। खरीददारी करने वालों में 86 फीसदी उपभोक्ता सचेत और जागरूक हैं। क्योंकि, वे खरीददारी से पूर्व पूरी जानकारी करते हैं। करीब 48 फीसदी लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी और लेन-देन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा। करीब 66 फीसदी उपभोक्ताओं को शिकायत निवारण प्रणाली का ज्ञान है और उनमें से अधिकांश ने शिकायत भी दर्ज कराई।

क्या आप खरीददारी से पहले जानकारी एकत्र करते है?

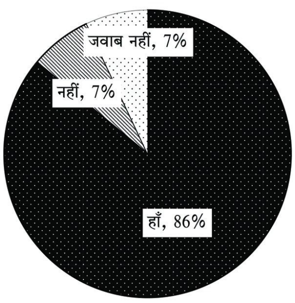

इस अंक में...

- सिर्फ कागजों में बनी पांच सौ सड़कें? 3
- भारत में बढ़ा भ्रष्टाचार 6
- किसानों की आमदनी बढ़ाने का वादा 7
- पानी 10 फीसदी मंहगा 9
- उद्योगों में बढ़े महिलाओं की भागीदारी 10

जैविक पदार्थों के प्रति बढ़ रही है जागरूकता

राजस्थान में जहां 86 फीसदी उपभोक्ता जैविक पदार्थों के उपभोग के प्रति जागरूक हैं। वहीं 91 फीसदी किसान रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से वाकिफ हैं। बावजूद इसके सिर्फ 19 फीसदी किसान ही प्रदेश में जैविक खेती कर रहे हैं। 'कट्स' द्वारा प्रदेश के 10 जिलों में चलाई जा रही प्रो-ओर्गेनिक परियोजना के तहत किए गए बेसलाइन सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ है। सर्वेक्षण में 10 जिलों से 192 ग्राम पंचायतों के 2439 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 644 किसान व 1795 उपभोक्ता शामिल थे।

प्रो-ओर्गेनिक (द्वितीय) परियोजना के तहत जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय परिचर्चा में यह जानकारी दी गई। सर्वे के मुताबिक 89 प्रतिशत उपभोक्ता यह जानते हैं कि जैविक पदार्थ रासायनिक खेती वाले पदार्थों से बेहतर होते हैं, वहीं 51 प्रतिशत उपभोक्ता जैविक पदार्थों को खरीदने के लिए ज्यादा कीमत चुकाने को भी तैयार रहे।

कार्यक्रम में नीलकमल दरबारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि), राजस्थान सरकार ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए भावी पीढ़ियों के हित में जैविक खेती की ओर फिर से लौटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 'कट्स' के सर्वे से यह बात सामने आई है कि 67 फीसदी किसानों को सरकारी अनुदान नहीं मिल पाता, इसके लिए सरकार की ओर से अनुदान बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।

'कट्स' निदेशक जॉर्ज चेरियन ने प्रो-ओर्गेनिक परियोजना के तहत अब तक किए गए कार्यों की जानकारी दी। राजदीप पारीक, कार्यक्रम अधिकारी ने परियोजना की गतिविधियों एवं सर्वेक्षण से सामने आए तथ्यों को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया। परिचर्चा में राज्य सरकार के कृषि विभाग के अधिकारी, जैविक खेती पर कार्य करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा परियोजना के तहत विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताओं सहित 75 से अधिक भागीदारों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

डिजिटल बाजार व्यवस्था पर गोष्ठी

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर जिला रसद कार्यालय और 'कट्स' मानव विकास केन्द्र चित्तौड़गढ़ के संयुक्त तत्वावधान में 'स्वस्थ एवं न्यायोचित डिजिटल बाजार व्यवस्था सुनिश्चित हो' विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में नगर विकासन्यास के सचिव सी.डी चारण ने मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि आज डिजिटल सेवाएं हम सब के लिए बुनियादी सेवा के रूप में उभर चुकी है। उपभोक्ताओं को जागरूक होकर डिजिटल सेवाओं से जुड़कर फायदा लेना होगा।

'कट्स' समन्वयक गौहर महमूद ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की जानकारी देते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डाला तथा एफएलसी कोर्डिनेटर अरविन्द पुरोहित ने ई-कॉमर्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत में वर्ष 2016 में इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या 28 प्रतिशत थी जो 2021 तक 60 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है।

कार्यक्रम में अग्रणी जिला प्रबन्धक संजय भारद्वाज ने बताया कि कई उपभोक्ता डिजिटल सेवाओं की जानकारी के अभाव में ठगे जा रहे हैं। हमें खरीददारी करते समय गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं का ही चयन करना चाहिए। नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक सचिन बाडेटिया ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि डिजिटल युग में हमें सावधानी रखते हुए किसी भी कॉल पर अपने बैंक खाता नंबर, आधार नंबर व एटीएम पासवर्ड बिल्कुल नहीं बताने चाहिए। इस अवसर पर हमारा हक, हमारा अधिकार नामक कलेण्डर का भी विमोचन किया गया।

पैसा दबाकर बैठे हैं विलफुल डिफॉल्टर

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार सितंबर 2017 तक देश के सरकारी बैंकों में एनपीए 7.34 लाख करोड़ रुपए था। वहीं प्राईवेट सेक्टर के बैंकों में एनपीए 1.03 लाख करोड़ रुपए था। बैंकों के एनपीए में सबसे बड़ी हिस्सेदारी कॉरपोरेट कंपनियों की है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2017 तक 1.1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि विलफुल डिफॉल्टर्स के पास है। यह बैंकों की खराब होती वित्तीय स्थिति की सबसे बड़ी वजह है। विलफुल डिफॉल्टर उन्हें कहा जाता है जिनकी कर्ज चुकाने की क्षमता है लेकिन वे देते नहीं है। पीएनबी में एसबीआई से चार गुना ज्यादा विलफुल डिफॉल्टर्स सिर्फ ज्वैलरी कारोबारी हैं। पीएनबी को ज्वैलरी डिफॉल्टरों के जरिए 1790 करोड़ रुपए का झटका लगा है। *(रा.प., 24.03.18)*

जनगणना के आंकड़े दबा रही सरकार

सत्ता में आए करीब साढ़े तीन साल से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी मोदी सरकार जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने के सवाल पर टालमटोल कर रही है। आठ दशक के बाद यूपीए सरकार ने 2011 में सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना करवाई थी।

यह देश के हर परिवार की जातीय और आर्थिक स्थिति को लेकर डाटा लेने के लिए जनगणना हुई थी। सामाजिक आर्थिक डाटा तो 2015 में सार्वजनिक हो गया मगर अभी तक जातिगत आंकड़े नहीं आए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष गताड़े के अनुसार सरकार का इन आंकड़ों को छिपाना बहुत गलत है। संस्था प्रतिष्ठान को डर है कि इन आंकड़ों के सार्वजनिक होने के बाद उसे अपनी राजनीतिक जुबान बदलनी पड़ेगी और राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिशों को झटका लगेगा। *(रा.प., 15.02.18)*

गोदामों के निर्माण में बरती सुस्ती

सहकारिता विभाग ने वर्ष 2017-18 के वार्षिक बजट में 100 नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम व कार्यालय निर्माण की स्वीकृति प्रदान की, लेकिन ज्यादातर समितियों में काम ही शुरु नहीं हुआ। जबकि इसके लिए प्रति समिति दस लाख रुपए, कुल दस करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।

इस सुस्त चाल को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने जनवरी तक इसे पूरा करने के निर्देश भी दिए, लेकिन ज्यादातर समितियों ने अभी भी काम शुरू नहीं किया है। *(दै.न., 03.01.18)*

सिर्फ कागजों में बनी पांच सौ सड़कें?

देश में ग्रामीण सड़कों की खस्ता हाल के पीछे विधायकों का भ्रष्टाचार है, जो अपनी बिरादरी वालों को ही सड़क बनाने के ठेके दे रहे हैं। वर्ष 2001 से 2013 के बीच इन विधायकों ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए जाति-बिरादरी वालों को 3592 करोड़ रुपए के ठेके दे दिए।

भ्रष्टाचार के चलते ज्यादातर सड़कें बनी नहीं या फिर केवल कागजों पर बन गई। इसमें नौकरशाहों के मिलीभगत की भी आशंका है। ऐसी 500 सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पैसा तो जारी हुआ लेकिन सड़कें नहीं बनीं। अमरीका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय और फ्रांस के पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। यह अध्ययन 'बिल्डिंग कनेक्शंसः पॉलिटिकल करप्शन एंड रोड कंस्ट्रक्शन इन इंडिया' नाम से हुआ। *(रा.प., 25.02.18)*

खातों में पड़ा रहा फण्ड

पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न मद से मिलने वाले फण्ड की भरमार है, लेकिन फिर भी उपलब्ध निधियों का शत-प्रतिशत उपयोग नहीं हो रहा है। संस्थाओं के लेखापरीक्षा जांच के दौरान सामने आया है कि गत पांच साल की अवधि के दौरान उपलब्ध निधियों का केवल 21 प्रतिशत ही उपयोग हुआ है।

वर्ष 2011-16 के दौरान उपलब्ध निधियों से किए गए खर्च दर्शाते हैं कि निधियों का उपयोग बहुत कम और उपलब्ध निधियों के 17.60 प्रतिशत से 23.73 प्रतिशत के बीच विस्तारित था। मार्च 2016 के अंत में 1093.11 करोड़ (2011-16 के दौरान आवंटित राशि का 60.73 प्रतिशत) का वृहद अप्रयुक्त शेष जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में अनुपयोजित पड़ा था। *(दै.न., 29.03.18)*

परीक्षा में बैठे नहीं उन्हें दे दी छात्रवृत्ति

अन्तहीन घोटालों के आरोपों से घिरे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का एक और कारनामा सामने आया है। अधिकारियों ने उन बच्चों में भी छात्रवृत्तियों की बंदरबाट कर दी जो परीक्षा में बैठे ही नहीं। यह मामला भी आईटीआई में दी गई छात्रवृत्तियों से जुड़ा है।

विभाग ने सत्र 2016-17 में ही परीक्षा में नहीं बैठने वाले 7730 छात्रों को 10.43 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति बांट दी। अब विभागीय अधिकारियों ने केन्द्र सरकार के लचीले नियमों को ढाल बनाकर चुप्पी साध रखी है। अधिकारियों की आंखों के सामने हर साल हजारों छात्र परीक्षा में बैठे बिना केवल कागजों में कॉलेज में प्रवेश लेकर छात्रवृत्ति उठा रहे हैं। जबकि केन्द्र सरकार के नियमों में लचीलापन केवल अपवाद स्वरूप मामलों के लिए है। *(रा.प., 08.02.18)*

दो करोड़ खर्च फिर भी नहीं मिला पानी

13वें वित्त आयोग से पंचायतीराज संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राशि मुहैया करवाई गई। करीब दो करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होने के बाद भी 51 ट्यूबवैलों से लोगों को पानी नसीब नहीं हो सका। पंचायतीराज संस्थाओं के लेखों की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि नोखा में दो करोड़ दस लाख रुपए की लागत से निर्मित 51 ट्यूबवैलों की स्थापना एवं विद्युत कनेक्शन के अभाव में अनुपयोगी रहने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने का उद्देश्य विफल रहा। *(दै.न., 27.03.18)*

लगाए करोड़ों पौधे, बचे 21 लाख ही

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2009 से 2012 के बीच तीन साल तक प्रदेश के सभी 33 जिलों में हरित राजस्थान अभियान चलाया गया था। अभियान के तहत तीन साल में कुल 4 करोड़ 38 लाख 51 हजार 38 पौधे लगाने पर 149 करोड़ 55 लाख 23 हजार रुपए खर्च होना बताया जा रहा है।

अब सरकार ने स्वीकार किया है कि 5 प्रतिशत यानी 21 लाख के करीब ही पेड़ बचे हैं। इसके अलावा डूंगरपुर में तो विश्व रिकार्ड का दावा करते हुए 12 घंटे में 6 लाख 1137 पौधे लगाए गए थे। अब वहां 86 हजार 664 पौधे ही जीवित बताए जा रहे हैं। मामलों में भ्रष्टाचार की आशंका के चलते बाबूलाल जाजू द्वारा लोकायुक्त एस.एस.कोठारी के समक्ष एक याचिका लगाई हुई है। *(दै.भा., 25.01.18)*

अब शिकायत करना भी हुआ महंगा

अब पंचायतीराज विभाग में अफसरों व नेताओं की शिकायत दर्ज करवाना 5 गुना तक महंगा हो गया है। शिकायत दर्ज कराने वाले परिवादी को अब दस के बजाय 50 रुपए के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा। इसके बाद सरपंच, प्रधान या जिला प्रमुख, ग्राम सेवक, बीडीओ या सीडीओ के खिलाफ जांच शुरू की जा सकेगी। मानना है कि इससे झूठी शिकायतों पर रोक लगेगी।

पंचायतीराज विभाग ने बढ़ाई गई राशि के बारे में संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जब तक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर परिवादी का शपथ पत्र नहीं आता, उस परिवाद पर विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाही नहीं की जाएगी। *(दै.भा., 05.03.18)*

आवास योजना की कछुआ चाल

मुख्यमंत्री, विभाग के मंत्री और मुख्य सचिव तक के निर्देश भी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लक्ष्यों को पूरा कराने में कारगर साबित नहीं हुए। इस वित्तीय वर्ष में करीब पौने पांच लाख आवासों की स्वीकृति जारी होने के बाद भी तकरीबन ढाई लाख आवास अभी प्रगतिरत श्रेणी में ही लम्बित पड़े हैं।

सालभर की कछुआ चाल के बाद अब ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने में इन ढाई लाख आवासों के निर्माण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। एक माह में इतने आवासों को पूरा करना संदेहप्रद है। *(दै.न., 07.03.18)*

छात्रावासों में पहुंची घटिया सामग्री

सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में घटिया सामग्री सप्लाई का मामला सामने आया है। सामग्री खरीद में करीब दो करोड़ रुपए का घपला होने की संभावना है। अधिकारियों ने नेशनल टैक्सटाइल कॉर्पोरेशन लि. के मार्फत कचरा व लुगदी भरे व कटे-फटे गद्दों व तकियों की खरीद-फरोख्त कर प्रदेश के 734 राजकीय छात्रावासों में सप्लाई कर दिया। गद्दों की लंबाई-चौड़ाई भी काफी कम है। बेडशीटें व दरियां आदि भी घटिया क्वालिटी की हैं।

पड़ताल करने पर चौंकाने वाली यह बात सामने आई कि मामले की जांच पूर्व अतिरिक्त निदेशक भी कर चुके हैं, लेकिन इस जांच रिपोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई।

(दै.भा., 06.02.18, 07.02.18)

लोक सूचना अधिकारी बेफिक्र

सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए 12 साल पहले लागू किए गए सूचना का अधिकार कानून की लोक सूचना अधिकारियों को न तो परवाह है और न ही कोई डर। कई विभागों के लोक सूचना अधिकारियों ने पहले तो लोगों द्वारा मांगी गई सूचनाएं ही नहीं दी। इस पर सूचना आयोग ने उन पर जुर्माना लगाया तो उसे भी नहीं चुकाया। राज्य के सूचना आयोग के पास 13 हजार से ज्यादा अपीलें लंबित हैं।

पिछले आठ साल में आयोग ने लोक सूचना अधिकारियों पर 3.21 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हाल ही आयोग की पिछले सालों की रिपोर्ट देखने पर सामने आया कि लोक सूचना अधिकारियों ने इसमें से केवल 81 लाख रुपए ही जमा कराए हैं। *(दै.भा., 06.03.18)*

गरीबों का 14 हजार क्विंटल गेहूं बेचा

गरीबों के लिए आवंटित 14 हजार क्विंटल गेहूं और 40 हजार लीटर केरोसीन रसदकर्मियों ने फर्जी महिला संगठन बनाकर ब्लैक में बेच दिया। अलवर जिले के करीब ढाई साल पुराने मामले में एसीबी ने रिटायर्ड जिला रसद अधिकारी अनिल जैन और प्रवर्तन निरीक्षक बनवारी लाल शर्मा समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

आरोपियों ने फर्जी तरीके से राशन की दो दुकानों का आवंटन कराया और एक साल में 40 हजार लीटर केरोसीन और 14 हजार क्विंटल गेहूं ब्लैक में बेच दिया। राशन हड़पने का यह खेल 2014 में शुरू हुआ और करीब एक साल तक चला। मामले में अमरदीप महिला समूह, शिकारी बास और गौरव महिला स्वयं सहायता समूह, साहबजोहड़, अलवर के नाम से दुकान आवंटित कर यह घोटाला किया गया। एसीबी मामले की जांच कर रही है। *(दै.भा., 19.01.18)*

बीपीएल का गेहूं उठाकर बेच दिया

करीब चार साल तक खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 92 हजार क्विंटल से अधिक गेहूं उठाया गया। इसे 1200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से डीलरों के साथ मिलीभगत कर 11 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। रसद विभाग के तत्कालीन डीएसओ और प्रवर्तन अधिकारी के खिलाफ यह शिकायत दर्ज हुई है।

मामला श्रीगंगानगर से जुड़ा है। डीएसओ सुनिल वर्मा ने एपीओ और प्रवर्तन निरीक्षक संदीप गौड़ ने निलंबन के बाद जिन राशन कार्डों के माध्यम से यह घोटाला किया, उन 10500 राशन कार्डों को खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर कर दिया। मामले की जांच कर रहे एसडीएम यशपाल आहूजा का कहना है कि दोनों आरोपियों को बुलाया गया है। घोटाले की शिकायत के बाद दोनों आरोपी निलंबित हैं। *(दै.भा., 23.01.18)*

पुलिस में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार

प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पुलिस महकमे में है। हाल ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने वर्ष 2017 के आंकड़े तैयार करके रिपोर्ट जारी की है। एसीबी ने वर्ष 2017 में 404 भ्रष्टाचार के केस दर्ज किए हैं।

इनमें ट्रैप, पद का दुरुपयोग, व आय से अधिक संपत्ति के मामले शामिल है। एक साल में एसीबी ने 96 मामले राजपत्रित अधिकारियों एवं 308 प्रकरण अराजपत्रित कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किए हैं।

अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से रिश्वत लेने या मांगने के बारे में 291 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इनमें से 42 प्रकरणों में राजपत्रित अधिकारियों व 249 प्रकरणों में अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेने के मामले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि एसीबी ने अन्य सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पुलिस महकमें में होना माना है।

पिछले एक साल में 83 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसीबी ने ट्रैप व पद का दुरुपयोग करने के मामले दर्ज कर गिरफ्तारियां की हैं। हालांकि इनमें सिर्फ एक ही राजपत्रित अधिकारी शामिल है। *(दै.भा., 02.01.18)*

नहीं सुधरे सरकारी विभागों के हालात

भ्रष्टाचार में राजस्व, यूडीएच, पुलिस व पंचायतीराज इस बार भी टॉप पर रहे हैं। इनमें से हर बार की तरह राजस्व विभाग नाकामियों में भी नंबर वन रहा है। यह लोकायुक्त एस.एस.कोठारी ने अपने 28 फरवरी तक के कार्यकाल की रिपोर्ट में उजागर किया है। यह रिपोर्ट प्रदेश के राज्यपाल कल्याण सिंह को सौंपी गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी विभागों के हालात वैसे ही हैं जैसे पिछले साल थे। यानी भ्रष्टाचार, काम में खामियां और आम जनता को समय पर राहत देने में विभागों के हालात सुधरे नहीं है।

लोकायुक्त की यह 32वीं रिपोर्ट है। प्रतिवेदन के अनुसार विभिन्न प्रकरणों में 407 लोकसेवकों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाइयां निर्णित हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा शिकायतें नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग की रही हैं।

(दै.भा., 21.03.18)

चिकित्सा विभाग में भ्रष्टाचार का खेल

प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने के नाम पर लाखों रुपए के लेन-देन और मेडिकल काउंसिल में ऑफिशियली बात करने के वार्तालाप से कई 'बड़ों' की पोल खुलती दिखाई दे रही है।

राज्य में नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं को मान्यता दिए जाने के नाम पर सरकार में प्रभावशाली व्यक्ति के बेटे के 20-20 लाख रुपए प्रति कॉलेज लेने और इसके बाद भी काम नहीं होने की बात है।

बातचीत का 20 मिनट का ऑडियो राजस्थान पत्रिका के पास है। इस ऑडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि निजी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दिलाने के नाम पर प्रभावशाली व्यक्ति के बेटे ने पहले 5 लाख, फिर 10 लाख और फिर 20 लाख रुपए प्रति कॉलेज ले रखे हैं। *(रा.प., 15.01.18)*

काले धन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

काले धन के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए केन्द्र सरकार ने बेनामी संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत देशभर में फ्लैट्स, प्लॉट, दुकानों, बैंक डिपॉजिट, एफडी, ज्वैलरी और वाहनों के रूप में बनाई गई 900 से ज्यादा बेनामी संपत्तियों को जब्त किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह बेनामी संपत्तियां 3500 करोड़ से भी ज्यादा की है। इनमें 2900 करोड़ से ज्यादा अचल संपत्ति है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्राजेंक्शन एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। यह कानून नवंबर 2016 से अमल में आया था। विभाग ने कहा है कि कालेधन और बेनामी लेनदेन के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

आयकर ने जांच निदेशालय के तहत देशभर में 24 बेनामी प्रोहिबिशन यूनिट्स बनाई है, ताकि बेनामी संपत्ति के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जा सके। *(रा.प., 12.01.18)*

घपले पकड़ने के बजाय ली रिश्वत

डूंगरपुर जिले के 55 उच्च माध्यमिक और माध्यमिक स्कूलों में वित्तीय घपलों की जांच की जिम्मेदारी जिन 8 ऑडिटरों को दी गई वे खुद ही रिश्वत लेते पकड़े गए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने उन्हें घपले दबाने की एवज में 10 से 15 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

एसीबी के मुताबिक ऑडिट टीम में शामिल लोगों ने लेखा रिकॉर्ड व कैशबुक में स्कूल स्तर पर हुए घपले को दबाने और ऑडिट आक्षेप नहीं लगाने के एवज में स्कूल के प्रिंसिपल और कैशियर से यह रिश्वत ली। इन ऑडिटरों की जेबों और होटल के कमरों से 81 हजार 735 रुपए बरामद किए गए।

(दै.भा., 22.03.18)

अब भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे- मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पहले लोग सोचते थे कि अमीर लोग और ताकतवर लोगों के साथ कुछ नहीं होता है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। तीन लोग जो पहले मुख्यमंत्री थे वे अब भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में हैं।

मोदी ने एनसीसी के 70 वें स्थापना दिवस के मौके पर युवाओं से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए यह बात कही।

उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ उनकी मुहिम में अपना योगदान दें। चीजों को खरीदने के लिए नगदी के इस्तेमाल को सीमित करें और डिजिटल लेन-देन के तरीकों का इस्तेमाल करें, इससे भ्रष्टाचार पर रोक लग सकती है।

(रा.प. एवं दै.न., 29.01.18)

भारत में बढ़ा भ्रष्टाचार

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वर्ष 2017 के लिए दुनियाभर के देशों का करप्शन इंडेक्स जारी कर दिया है। भ्रष्टाचार के मामले में भारत दो पायदान फिसलकर 183 देशों में 81वें स्थान पर जा पहुंचा है। वर्ष 2016 में भारत 79वें नंबर पर था। रैंकिंग के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 0 (सबसे ज्यादा भ्रष्ट) से 100 अंक (भ्रष्टाचार मुक्त) के पैमाने पर 183 देशों में सरकारी संगठनों और कंपनियों में भ्रष्टाचार का आकलन किया है। भारत को इस बार भी 2016 के बराबर 40 अंक मिले हैं। जिस देश का जितना ज्यादा स्कोर होता है वह उतना कम भ्रष्ट माना जाता है।

न्यूजीलैंड का स्कोर 89 है और वह सबसे कम भ्रष्ट माना गया है। कम भ्रष्ट देशों में इसके बाद डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीट्जरलैंड का नंबर आता है। सोमालिया का स्कोर 9 है और वह सबसे भ्रष्ट देश है। भारत का स्कोर 40 है। पड़ोसी देश चीन का स्कोर 41 है, वह भारत से कम भ्रष्ट है। जबकि श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में भारत से ज्यादा भ्रष्टाचार है। *(दै.भा. एवं न.नु., 23.02.18)*

नहीं चाहते भ्रष्टाचार खत्म हो

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई के बावजूद रिश्वतखोर अधिकारी व कर्मचारी आसानी से बच निकलते हैं। इसकी बड़ी वजह है उनके ही विभाग से उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति देने से मनाही कर देना है। एसीबी के प्रदेशभर में 133 मामलों में संबंधित विभागों ने अभियोजन स्वीकृति नहीं दी या लम्बे समय से विचाराधीन रखी हुई है।

बड़े अचरज की बात यह है कि संबंधित विभागों के अधिकारी - कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े जाने के बावजूद संबंधित विभाग उन पर मेहरबान रहते हैं। वे उन्हें विभागीय जांच में क्लीन-चिट दे देते हैं। साथ ही एसीबी को भिन्न-भिन्न कारण बताकर अभियोजन स्वीकृति देने से इनकार कर देते हैं।

(रा.प., 17.02.18)

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
बांसवाड़ा	मोहन कुमार निनामा	एएसआई, पुलिस सदर थाना, बांसवाड़ा	10,000	दै.भा. एवं दै.न., 11.01.18
राजसमंद	श्रीराम मिश्रा	खाद्य निरीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय	10,000	दै.भा. एवं दै.न., 11.01.18
भीलवाड़ा	गोपाला राम दीपक एवं निर्मल शर्मा	अधीक्षण भू-वैज्ञानिक, भूगर्भ शाखा, खान विभाग दलाल	10,000	दै.भा. एवं दै.न., 11.01.18
बांसवाड़ा	नरेश कुमार टेलर	कार्यवाहक प्राचार्य, राजकीय सी.सै.स्कूल, मोटीटिंबी	25,000	दै.भा. एवं दै.न., 19.01.18
बूंदी	ग्यारसी लाल नागर	कांस्टेबल, पीए सेक्शन, एस.पी ऑफिस, बूंदी	20,000	दै.न., 30.01.18
जोधपुर	कन्हैया लाल श्याम लाल विश्नोई	एक्सईएन, विजिलेंस टीम, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ड्राईवर, विजिलेंस टीम, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर	20,000	दै.न. एवं दै.भा., 30.01.18
जैसलमेर	गंगाराम	ग्राम सेवक, राघवा ग्राम पंचायत समिति	9,000	रा.प., 07.02.18
श्रीगंगानगर	राधेश्याम	एसआई, जवाहर नगर थाना, श्रीगंगानगर	11,000	दै.भा., 10.02.18
अलवर	नरेन्द्र खण्डेलवाल	एईएन, मनरेगा, तिजारा पंचायत समिति, अलवर	7,000	दै.भा., 10.02.18
राजसमंद	डॉ. प्रकाश सिरसट	विकास अधिकारी, भीम पंचायत समिति	7,000	दै.न., 20.02.18
भरतपुर	समय सिंह गुर्जर	विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत समिति	40,000	दै.न., 27.02.18
झुंझुनूं	अनिल कुमार	कनिष्ठ अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.	7,000	दै.न., 27.02.18
भरतपुर	बसंत सिंह करतार सिंह	सब इंस्पैक्टर, पहाड़ी थाना, भरतपुर कांस्टेबल, पहाड़ी थाना, भरतपुर	1,00,000	दै.भा. एवं दै.न., 08.03.18
नागौर	किशन लाल कुमावत	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका कुचामनसिटी	2,00,000	रा.प., 15.03.18
झुंझुनूं	भरत कुमार हरितवाल श्रवण कुमार	ईओ, मंडावा नगरपालिका, झुंझुनूं जेईएन, मंडावा नगरपालिका, झुंझुनूं	39,000 15,000	दै.भा., 23.03.18
हनुमानगढ़	संदीप विश्नोई विनोद कुमार	ईओ, संगरिया नगरपालिका, हनुमानगढ़ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, संगरिया नगरपालिका	50,000	दै.भा एवं दै.न., 24.03.18

निर्मल चरित्र हो पवित्र आत्मा! भ्रष्टाचार का तभी खात्मा!!

किसानों की आमदनी बढ़ाने का वादा

केन्द्रीय बजट में किसानों व कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। किसानों को एक बड़ी राहत देते हुए केन्द्र सरकार ने कृषि ऋण के लक्ष्य को 10 प्रतिशत बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। धान जैसी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उत्पादन की लागत से 50 प्रतिशत ऊपर तय करने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा है कि सरकार का ध्यान किसानों की आय बढ़ाने पर है। रबी की फसलों के लिए एमएसपी में पहले ही बढ़ोतरी हो चुकी है। सरकार कृषि जिंसों का निर्यात बढ़ाने के लिए भी कदम उठाएगी।

राजस्थान के बजट में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लघु और सीमांत किसानों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने ऐसे किसानों के 30 सितंबर 2017 तक बकाया अल्पकालिक फसली ऋण में से 50 हजार रुपए तक के कर्ज माफ करने की घोषणा की है। इससे सरकार पर करीब 8 हजार करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। सरकार ने राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग का भी गठन किया है जो स्थाई संस्थान के रूप में काम करेगा।

किसानों को फसल उपज का वाजिब दाम मिले इसके लिए समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर लाभ पहुंचाया जा रहा है। भण्डारण क्षमता को बढ़ाने के लिए गोदाम बनाने पर 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वर्ष 2018-19 से किसानों का भूमि पर लगने वाला लगान माफ किया जाएगा। इसके अलावा भी किसानों को बहुत सी सहूलियतें दी गई हैं, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

(रा.प. एवं दै.भा., 02.02.18, 13.02.18)

ग्रामीण विकास पर ज्यादा ध्यान

केन्द्रीय बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19 हजार करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का जाल बिछेगा। गांवों की सड़कों को कृषि बाजारों से जोड़ा जाएगा। 22 हजार हॉज कृषि बाजार बनेंगे। आजीविका मिशन के लिए 1366 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चार करोड़ गरीबों के घर 'सौभाग्य' योजना के तहत रोशन होंगे। इसके लिए 2750 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के जरिए 3800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के लिए 7000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 27506 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में जानकारी दी है कि प्रदेश में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए 52 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 766 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण गौरव पथ अथवा मिसिंग लिंक सड़कों को जोड़ा जाएगा। जनवरी 2012 तक के लंबित 2 लाख कृषि कनेक्शन आगामी वर्ष में दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा भी ग्रामीण विकास को पंख लगाने के लिए बहुत सी घोषणाएं की गई है।

(रा.प. एवं दै.भा., 02.02.18, 13.02.18)

भारत में बढ़ती जा रही है गरीबी

गैर सरकारी संगठन ऑक्सफेम ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में गरीब और ज्यादा गरीब हो रहे हैं। यहां असमानता बीते तीन दशकों में बढ़ रही है। रिपोर्ट में इन हालात के लिए सरकार की असंतुलित नीतियों को जिम्मेदार बताया गया है। कहा गया है कि भारत में धनाढ्यों ने देश में सृजित संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा 'सांठ-गांठ वाले पूंजीवाद' या 'बपौती' में हासिल किया है। वहीं नीचे के तबके की आय में हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है।

ऑक्सफेम इंडिया की सीईओ निशा अग्रवाल ने कहा है कि असमानताएं उदारीकरण सुधार पैकेजों के बाद अपनाई नीतियों का परिणाम है। *(न.नु., 24.02.18)*

सभी किसानों का होगा कर्जा माफ

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश के अब सभी श्रेणी के किसानों के सहकारी बैंकों से लिए गए 50 हजार रुपए तक के कर्जे माफ कर दिए हैं। पहले मूल बजट में लघु और सीमांत श्रेणी के किसानों के कर्जे ही माफ करने की घोषणा की गई थी। सभी किसानों के 50 हजार के कर्ज माफ करने की इस घोषणा से करीब ढाई से तीन लाख और किसानों को फायदा मिलेगा।

सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया ऋण माफी योजना का लाभ 30 सितंबर 2017 तक ऋण लेने वाले किसानों को मिलेगा। जिन किसानों ने इसके बाद ऋण जमा करा दिया हो, तो भी उन्हें ऋण माफी योजना का लाभ मिलेगा। *(दै.न. एवं रा.प., 07.03.18)*

चारागाह भूमि विकसित करेगी सरकार

राज्य सरकार ने बंजर और चारागाह भूमि को उपयोगी बनाने के लिहाज से नए वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश की हर पंचायत समिति में 5 से 10 हेक्टेयर भूमि पर चारागाह विकास की कार्ययोजना तैयार की है। इसके लिए पहले 90 ब्लॉक में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कार्य शुरू किए जाएंगे। योजना के तहत बंजर भूमि पर पौधारोपण कराया जाएगा।

इस कार्य के लिए बायोफ्यूल प्राधिकरण को नोडल ऐजेंसी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। चारागाह भूमि विकास के लिए जिला परिषदों के माध्यम से जमीन चिन्हीकरण की कार्रवाई और विकास कार्ययोजना तैयारी के लिए उच्चस्तरीय बैठक कर मुहर लगाई जाएगी।

(दै.न., 12.03.19)

अब समय पर खर्च होगा एमएलए फंड

ग्रामीण इलाकों में विधायक स्थानीय विकास योजना का पैसा समय पर खर्च नहीं होने पर राज्य सरकार ने नाराजगी जताई है। यह राशि खर्च करने के लिए अब सरकार ने जिला परिषदों को समयबद्ध कार्यक्रम जारी कर उस पर सख्ती से पालना करने को कहा है।

विधायक फंड से जारी विकास कार्यों पर योजना के तहत अधिकतम पांच दिन में प्रशासनिक स्वीकृति एवं 18 दिन में तकनीकी स्वीकृति जारी करना अनिवार्य होगा। इसके बाद सात दिन में वित्तीय स्वीकृति जारी करना आवश्यक है। *(दै.न., 04.01.18)*

एलईडी से जगमग होंगे गांव

स्मार्ट विलेज के लिए चयनित गांवों में सरकार ने इस बार सोलर लाइट के बजाय एलईडी लाइटें लगाने का फैसला लिया है। स्मार्ट गांव बनाने की बजट घोषणा में सरकार ने तीन हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों को चयनित किया है। इसमें प्रदेश के 3275 गांव आएंगे।

इनमें से प्रत्येक गांव में सौ से सवा सौ लाइटों की खरीद की जानी है। ऐसे में पंचायतें करीब साढ़े तीन से चार लाख स्ट्रीट लाइटें खरीदेगी। तीन साल पहले पंचायतों में सोलर लाइट खरीद में काफी अनियमितताएं सामने आई थी, मद्देनजर इस बार सरकार इस योजना में फूंक-फूंक कर कदम रख रही है।

(रा.प., 14.01.18)

अंडरग्राउंड होंगे बिजली के तार

जयपुर स्मार्ट सिटी लि. के आवेदन पर बिजली के तारों को शीघ्र अण्डरग्राउण्ड कराया जाएगा। विधानसभा में ऊर्जा राज्यमंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने यह जानकारी प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुरेन्द्र पारीक समेत अन्य विधायकों के पूरक प्रश्नों के जवाब में दी।

उन्होंने बताया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आवेदन पर मांगपत्र जारी किया जा चुका है। पहले चरण में 16.81 करोड़ व दूसरे चरण में 17.9 करोड़ रुपए के काम कराए जाएंगे। पहले चरण के लिए टेंडर जारी कर चुके हैं और शीघ्र ही आशय पत्र जारी हो जाएगा। दूसरा टेंडर 15 दिन में कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा जयपुर शहर के लिए 294 करोड़ रुपए मिले हैं, जिनमें से 112 करोड़ रुपए सिस्टम इम्प्रूवमेंट पर और 181 करोड़ रुपए चारदिवारी के महत्वपूर्ण स्थलों पर खर्च किए जाएंगे। *(रा.प.,08.02.18)*

स्मार्ट कंट्रोल से बची बिजली

सड़कों पर स्मार्ट लाइटें लगाने के नवाचार से बिजली की बड़ी बचत होनी शुरू हो गई है। सेंसर से संचालित होने वाली स्मार्ट लाइट से 45 प्रतिशत तक बिजली की बचत हुई है।

इस आंकड़े ने जेडीए अफसरों से लेकर सरकार के नुमाइंदों की बांछे खिला दी है। इसमें जगतपुरा के महल रोड पर सामान्य रोड लाइट से होने वाली बिजली खपत और सेंसर युक्त स्मार्ट लाइट के बाद खपत का चार माह का आकलन किया गया है।

हालांकि, सात जगह और स्मार्ट लाइटों से सड़कों को रोशन किया गया है, लेकिन वहां से अभी बिजली बचत का आंकड़ा आना बाकी है। *(रा.प., 19.01.18)*

सूर्य ऊर्जा का लक्ष्य पूरा कर लेंगे

भारत वर्ष 2017-18 के अंत तक सूर्य ऊर्जा क्षमता में 10 हजार मेगावाट वृद्धि का लक्ष्य अर्जित कर लेगा। यह वर्ष 2016-17 के दौरान हुई वृद्धि के मुकाबले दोगुनी होगी। वर्ष 2017-18 के दौरान फरवरी माह तक भारत की कुल सोलर पॉवर क्षमता बढ़कर 19 हजार 584 मेगावाट हो गई है। वर्ष 2017-18 के अंत तक कुल स्थापित क्षमता बढ़कर 22 हजार मेगावाट हो जाने की संभावना है।

वर्ष 2016-17 के दौरान देश में 5526 मेगावाट क्षमता का सृजन हुआ था। वर्ष 2016-17 के अंत तक देश की सोलर पॉवर बढ़कर 12 हजार 288.8 मेगावाट हो गई थी। इसके बाद फरवरी 2018 तक 7295 मेगावाट क्षमता का नया सृजन हुआ है। साल के अंत तक 2700 मेगावाट क्षमता का सृजन और हो जाएगा। इसके बाद क्षमता में और भी तेजी से विस्तार होने की संभावना है। *(न.नु., 31.03.18)*

निजी हाथों में नहीं जाएगी बिजली

राज्य सरकार ने जयपुर डिस्कॉम को निजी हाथों में सौंपने का फरमान वापस ले लिया है। चुनावी साल में सरकार उपभोक्ताओं का कोई विरोध नहीं झेलना चाहती। ऐसे में सरकार द्वारा डिस्कॉम के उपकेन्द्रों पर बिजली की व्यवस्था निजी हाथों में नहीं सौंपने का निर्णय लिया गया है।

जयपुर डिस्कॉम की ओर से 13 सर्किल के समस्त 1603 जीएसएस को ठेके पर देने की निविदा को अब निरस्त कर दिया गया है। इस निर्णय से जयपुर डिस्कॉम के उपकेन्द्रों के आठ हजार तकनीकी हेल्परों के सामने भी नौकरी का संकट नहीं रहेगा। *(रा.प., 27.02.18)*

बिजली बनाएंगे एकजुट होकर 121 देश

भारत और फ्रांस ने मिलकर दो साल पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस(आईएसए) का गठन किया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने 11 मार्च 2018 को आइएएस के पहले सम्मेलन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस सम्मेलन में फ्रांस, श्रीलंका, बांग्लादेश व 23 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 10 देशों के मंत्री समेत 121 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसे दुनिया के सोलर ऊर्जा सेक्टर में भारत और फ्रांस की बड़ी पहल माना जा रहा है।

राष्ट्रपति मैक्रो ने सम्मेलन में बताया कि फ्रांस 2022 तक आईएएस को 5600 करोड़ रुपए का फंड देगा। इसके जरिए 2030 तक 1000 गीगावॉट सोलर बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। इस बिजली की कुल कीमत 65 लाख करोड़ रुपए होगी। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी के स्त्रोतों से 175 गीगावाट बिजली पैदा करने लगेगा। *(दै.भा.एवं रा.प., 12.03.18)*

सूर्यदेव की कृपा से पक जाए खाना...

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मिर्जापुर में 75 मेगावाट सौर ऊर्जा केन्द्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि फ्रांस और भारत मिलकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसके तहत हाल ही अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के 62 देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और समाज में वंचित लोगों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने के लिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है।

उन्होंने कहा है कि सौर ऊर्जा से देश में बदलाव आ सकता है। हम तो चाहते हैं कि सौर ऊर्जा के चूल्हे पर खाना पके। गरीब माताओं और बहिनों की मदद हो सके। सूर्य देवता की कृपा से खाना पक जाए और एक पैसा भी न खर्च हो। उन्होंने नौजवानों से अपील करते हुए कहा इस क्षेत्र में आधुनिकतम तकनीक विकसित की जानी चाहिए। *(दै.न. एवं न.नु., 13.03.18)*

बिजली छीजत, बिजली चोरी ! उपभोक्ता पर है दोनों भारी !!

पानी 10 फीसदी मंहगा

प्रदेश में एक अप्रेल से पानी महंगा हो जाएगा। राज्य सरकार की ओर से ढाई साल पहले एक पॉलिसी जारी कर प्रावधान कर दिया गया कि हर साल एक अप्रेल को पानी की दरों में स्वतः ही 10 फीसदी वृद्धि की जाएगी। इस नीतिगत निर्णय के अनुसार ही यह बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है।

यह बढ़ोतरी घरेलू कनेक्शन में आठ हजार लीटर तक 1.89 रुपए प्रति हजार लीटर होगी। इसी तरह औद्योगिक कनेक्शन की दर अब 38.50 की जगह 42.35 रुपए प्रति हजार लीटर होगी। इसके अलावा नये घरेलू कनेक्शन के लिए अब 550 रुपए की बजाय 605 रुपए चुकाने होंगे। *(रा.प.एवं दै.न., 31.03.18)*

33 साल प्यास बुझाने का प्लान तैयार

बीसलपुर बांध से जयपुर शहर में 33 साल बाद भी बिना रुकावट के पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए जलदाय विभाग 1000 करोड़ रुपए की लागत से दूसरी लाइन बिछाने का काम इसी साल शुरू कर देगा।

प्लान के मुताबिक सूरजपुरा में 200 एमएलडी का फिल्टर प्लांट व जयपुर में बालावाला तक 93 किलोमीटर लम्बी लाइन बिछाई जाएगी। इससे गुलाबी नगर में पेयजल सप्लाई की क्षमता प्रतिदिन 950 एमएलडी पहुंच जाएगी।

इसके बाद उस 32 फीसदी आबादी को भी बीसलपुर का पानी मिलेगा, जो अभी तक भूजल पर निर्भर है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की मियाद करीब ढ़ाई साल मानी जा रही है। बांध में पानी की आवक को बढ़ाने के लिए ब्राह्मणी-बनास परियोजना पर भी काम होगा जहां से बीसलपुर तक पानी लाया जाएगा। *(रा.प., 14.02.18)*

प्रदेश में पेयजल सर्वाधिक दूषित

केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अनुसार देश में सर्वाधिक दूषित पेयजल में राजस्थान पहले स्थान पर है। यहां हर पांचवां व्यक्ति किसी न किसी तरह का हानिकारक केमिकल युक्त दूषित पानी पीने को मजबूर है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल के तहत केन्द्र ने पिछले चार साल में राज्य को 3166.15 करोड़ रुपए पेयजल व्यवस्था के लिए आंवटित किया, जिसमें से शुद्ध पेयजल पर 2947 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। केन्द्र ने पाइप लाइन आधारित पेयजल सप्लाई की सलाह दी है। प्रदेश में अभी भी करीब 19 हजार 893 बसावट में रहने वाले लोगों को पूरी तरह शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी में फ्लोराइड और नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा है। *(रा.प. एवं दै.न., 04.01.18)*

अब अटल भूजल योजना

केन्द्र सरकार गिरते वॉटर लेवल समस्या के निदान के लिए अटल भूजल योजना ला रही है। यह जानकारी देते हुए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य अति जल दोहन वाले क्षेत्रों में टिकाऊ भूजल प्रबंधन और इसके लिए सामुदायिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है।

इन क्षेत्रों में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाके शामिल हैं। गडकरी ने बताया कि यह योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका अनुमानित आवंटन 8000 करोड़ रुपए है। इसे विश्व बैंक के सहयोग से पूरा किया जाएगा। *(न.नु., 16.03.19)*

जीपीएस लैस, फिर भी बिक रहा पानी

जलदाय विभाग की ओर से टैंकरों को जीपीएस से लैस किए जाने के बावजूद टैंकर चालकों की मनमानी नहीं थम रही है। वे पंप हाउस से खाली टैंकर गुजार कर भुगतान उठा रहे हैं। अगर टैंकर भर लिया जाता है तो इसे मनमाने दाम पर बेचा जा रहा है। सांगानेर के मुहाना मोड़ पंप हाउस आने वाले टैंकर चालक यही खेल कर रहे हैं। ऐसे में क्षेत्र की प्यासी जनता को पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है।

टैंकरों पर निःशुल्क जल वितरण लिखा होने के बावजूद 260 से 300 रुपए तक प्रति टैंकर पानी बेचा जा रहा है। सशक्त मॉनिटरिंग के अभाव में टैंकर चालकों ने जीपीएस जैसी अत्याधुनिक निगरानी तकनीक को भी धता बता दिया है। पूरे शहर में निःशुल्क जल वितरण टैंकरों की निगरानी नहीं होने से यह खेल चल रहा है। *(रा.प., 01.01.18)*

टैंकरों से बुझेगी लोगों की प्यास

गर्मियों में प्रदेश के ग्रामीण और ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पीने के पानी की समस्या सामने आती रही है। जलदाय विभाग का मानना है कि इस बार कम बारिश के चलते प्रदेश के करीब 14 जिलों में पीने के पानी की किल्लत सामने आने की आशंका है। इन जिलों के करीब 150 कस्बों में पानी की परेशानी को देखते हुए विभाग द्वारा टैंकरों के माध्यम से पेयजल मुहैया करवाया जाएगा।

इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी योजना बनाई गई है। जलदाय विभाग का मानना है कि निर्माणाधीन वृहद पेयजल योजनाओं के पूरा होने पर पीने के पानी की समस्या का स्थाई समाधान हो सकेगा। *(दै.न., 21.03.18)*

किसानों के लिए कुसुम योजना

किसानों की आय दोगुना करने के मकसद से उन्हें सौर पम्प उपलब्ध कराने की केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी कुसुम योजना की रूपरेखा तैयार हो गई है। ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह ने बताया कि जल्द ही इसे मंत्रीमंडल के समक्ष रखा जाएगा। बजट घोषणा के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2017-18 में 17 लाख 50 हजार सौर पम्प लगाने की योजना है।

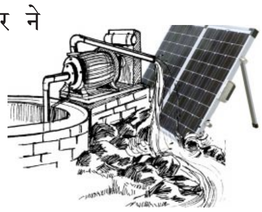

केन्द्र सरकार ने इसके लिए 48 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। जबकि शेष 28 हजार 250 करोड़ रुपए की राशि राज्यों द्वारा ऋण के माध्यम से या स्वयं किसानों द्वारा दी जानी है। पहले चरण में साढ़े सात लाख सौर पम्पों के वितरण की योजना है। *(दै-.न., 21.02.18)*

प्रधानमंत्री ने देश को दी दो बड़ी सौगातें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व महिला दिवस पर झुंझुनूं जिले में दो बड़े अभियानों का शुभारंभ किया। पहला बेटी को आन-बान और शान बताते हुए उन्होंने देश के 640 जिलों के लिए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की।

दूसरा देश के 325 जिलों में नौ हजार करोड़ रुपए के राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि मिशन के पहले चरण में करीब दस करोड़ महिला और बच्चों को इससे जोड़ा गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि बेटी हमारी अमानत है, वह सशक्त होगी तो राष्ट्र और प्रदेश सशक्त होगा। प्रदेश में दोनों अभियानों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

महिला व बाल विकास पर एक नजर

केन्द्रीय बजट में 8 करोड़ गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देने की घोषणा की गई है। पहले साल यह लक्ष्य 5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का था। इस बार लक्ष्य बढ़ाया गया है। वहीं राजस्थान के बजट में आंगनबाड़ी महिला कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। मानदेय कर्मियों के कल्याण के लिए सामूहिक बचत आधारित बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम भी अब सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

ग्रामीण बालिका और महिलाओं को मुफ्त सेनेटरी पैड का वितरण होगा। महिला कर्मचारियों को पूरी सेवा अवधि में 18 साल से कम आयु के बच्चों की देखभाल के लिए अधिकतम 2 साल की चाइल्ड केयर अवकाश का प्रस्ताव रखा गया है। स्वयंसेवी महिला संगठनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कई प्रावधान बजट में है।

(रा.प. एवं दै.भा., 02.02.18, 13.02.18)

बच्ची से दुष्कर्म पर मौत की सजा

प्रदेश में अबोध बालिकाओं के साथ बलात्कार करने वालों को अब मौत की सजा दी जा सकेगी। राज्य विधानसभा में मृत्युदंड देने के प्रावधान वाला दंड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक 2018 ध्वनिमत से पारित हो गया है। अब इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद ही यह कानून राज्य में लागू होगा।

बारह साल से कम उम्र की बालिकाओं के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार करने वालों के लिए यह कड़ा कानून लाया गया है। कानूनन ऐसे अपराधियों को कम से कम चौदह साल का कठोर कारावास, जो आजीवन तक हो सकेगा। अपराध की गंभीरता को देखते हुए बलात्कारियों को मृत्युदंड तक की सजा हो सकेगी। सामूहिक बलात्कार में शामिल सभी अपराधियों को कठोर कारावास में कम से कम 20 साल की सजा या आजीवन कारावास तथा मृत्युदंड का प्रावधान भी किया गया है। *(रा.प., दै.भा. एवं दै.न., 10.03.18)*

लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार

प्रदेश में पांच साल से कम आयु के 39.1 फीसदी बच्चे अविकसित हैं। शहरी इलाकों में यह आंकड़ा 33 फीसदी का है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 40.8 फीसदी तक है। कुपोषण की यह सच्चाई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-4 में सामने आई है। कम वजन व अविकसित होने से बच्चों में कुपोषण की समस्या बढ़ रही है। इससे न केवल बच्चों का विकास प्रभावित हो रहा है, बल्कि नवजात बच्चों की मौत भी हो रही है। छोटे बच्चों में कुपोषण का मुख्य कारण खान-पान की कमी के साथ स्वच्छता का नहीं होना भी है। गांवों में अभी भी परिवारों में स्वच्छता रखने की आदत नहीं हैं।

(रा.प., 28.02.18)

काम सरकार करेगी, आप बैठे रहेंगे...

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कहना है कि सब काम सरकार करेगी और आप बैठे रहेंगे, अब ये नहीं चलेगा। आपको भी देश के विकास के लिए आगे आना होगा। सरकारी योजनाओं में आपको भी भागीदारी निभानी चाहिए।

उन्होंने महिला आरक्षण को सही ठहराते हुए कहा कि लोग शिकायत करते हैं कि पंचायत चुनावों में महिलाएं सरपंच बन जाती है, उनके काम उनके पति करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें महिला पंच-सरपंचों के काम में दखलन्दाजी नहीं करनी चाहिए। महिलाएं अच्छा काम कर रहीं है। उन्हें हमें शिक्षित कर गांव के विकास में भागीदार बनाना होगा।

(दै.भा.08.01.18)

कृषि में बढ़ी महिलाओं की हिस्सेदारी

केन्द्र सरकार ने कृषि संबंधी सभी योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास संबंधित गतिविधियों के आवंटन में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित किया है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं को जमीन, तकनीक और पूंजी तक की पहुंच देने की व्यवस्था की गई है।

इससे देश में खेती-किसानी, उद्यमों और श्रम क्षेत्रों में महिलाओं कि हिस्सेदारी बढ़ी है। कृषि उत्पादन, फसल कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन के सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी को जरूरी माना गया है। कृषि में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देते हुए सरकार ने हर साल 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस घोषित किया है।

(दै.न., 05.03.18)

उद्योगों में बढ़े महिलाओं की भागीदारी

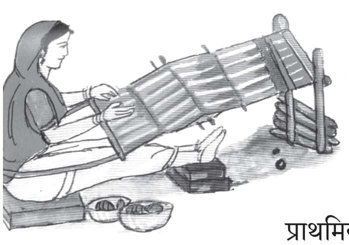

केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि महिलाओं में स्वरोजगार की भावना पैदा करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महिलाओं को हाशिये से निकालकर विकास में भागीदार बनाना चाहते हैं। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को प्राथमिकता दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के तहत अब तक करीब 9 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ऋण दिया गया है, जिसमें 70 फीसदी ऋण महिलाओं को दिया है। ऋण के वापस चुकाने में भी महिलाएं आगे हैं। वर्तमान में उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी मात्र 14 फीसदी है। इसे बढ़ाकर कम से कम 40 फीसदी तक लाना होगा। *(दै.न., 08.01.18)*

सड़क सुरक्षा

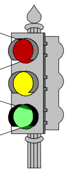

ज्यादा मौतों का कारण है सिर में चोट

राजस्थान में हर साल करीब 10 हजार लोगों की जान सड़क हादसों में जा रही है। दुर्घटनाओं के समय सबसे ज्यादा मौतों का कारण सिर में लगी चोट होती है। यही नहीं सिर में चोट लगने से घायल हुए लोगों में से 20 प्रतिशत लोग बच तो जाते हैं लेकिन वे दूसरी गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जिसमें ब्रेन ट्यूमर और मिर्गी होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। हेड इंजरी का सीधा कनेक्शन ब्रेन स्टेम एरिया से होता है। सिर के किसी भी हिस्से में लगी कोई भी चोट खतरनाक होती है। लेकिन ब्रेन स्टेम एरिया ज्यादा संवेदनशील होता है, क्योंकि शरीर की सभी नसों का संपर्क यही से होता है।

> ***कभी भी लापरवाही नहीं बरतें***
>
> *नारायणा हॉस्पिटल के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. के.के.बंसल ने बताया कि कभी भी सिर पर लगी चोट को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। वाहन चलाते समय हमेशा सिर पर हेलमेट पहनें। हमारे शरीर में दिमाग बहुत नाजुक अंग होता है। हालांकि यह खोपड़ी से कवर होता है जिस कारण यह सुरक्षित रहता है। लेकिन इसके बावजूद अपने सिर का ख्याल रखना अतिरिक्त जरूरी है और चोट लगने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।*

नारायणा हॉस्पिटल के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. प्रशांत सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली अधिकतर मौत हेलमेट नहीं पहनने के कारण हो रही है। सरकार की ओर से हेलमेट पहनने पर सख्ती व अभियान चलाने के बाद भी लोगों में जागरूकता का अभाव है। सिर पर चोट लगने से मरने वालों में युवाओं की संख्या ज्यादा है। *(दै.न., 20.03.18)*

जन स्वास्थ्य

हेल्थ केयर से सुधरेगी गरीब की सेहत

केन्द्र सरकार के बजट में गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों के लिए हेल्थ केयर बीमा योजना लागू करने की घोषणा की गई है। इसे देश के इतिहास में पहली और दुनिया की सबसे बड़ी योजना बताया जा रहा है। कहा गया है कि 50 करोड़ जरुरतमंद परिवार इस योजना का फायदा ले सकेंगे। मेडिकल बीमा के तहत ऐसे परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। यदि यह योजना सही रूप से लागू होती है, तो यह ऐसे परिवारों के लिए बेहद लाभदायक होगी।

राजस्थान के बजट में राज्य के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में नई कैथ लेब व जयपुरिया अस्पताल में स्वाइन फ्लू लैब की स्थापना होगी। राज्य में 28 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे तथा 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में तब्दील किया जाएगा। इन पर 120 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धौलपुर में नया मेडिकल कॉलेज बनेगा। निजी क्षेत्र में भी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना होगी। मातृ एवं शिशु इकाइयों में 18 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन सिस्टम स्थापित होंगे। चिकित्सकों, नर्सों व महिला कार्यकर्ताओं की नई भर्ती भी की जाएगी। *(रा.प. एवं दै.भा., 02.02.18, 13.02.18)*

पर्यावरण

खराब आबोहवा घटा रही लोगों का जीवन

प्रदूषण के कारण देश में सबसे अधिक जानें राजस्थान में जा रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की हाल ही जारी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। भारत में ब्रोंकाइटिस, श्वास के संक्रमण और अस्थमा में सबसे अधिक मौतें राजस्थान में हो रही है। आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक प्रति लाख 111 मौतें प्रति वर्ष ब्रोंकाइटिस यानी क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज(सीओपीडी) से हो रही है।

अस्थमा से भी पूरे देश में सबसे अधिक प्रति लाख 23 मौतें हो रही हैं। वहीं श्वास के संक्रमण से होने वाली मौतों में भी राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है। श्वास संक्रमण से राजस्थान में प्रति लाख 52 मौतें सालाना हो रही है। जबकि श्वास के कारण सबसे अधिक प्रति लाख 53 मौतें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं।

एसएमएस के पूर्व सीएमओ एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ डॉ. वीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि प्रदूषण राजस्थान में सबसे बड़ा हत्यारा बनकर उभर रहा है। इनडोर प्रदूषण और माइनिंग इंडस्ट्री का प्रदूषण जानलेवा बना हुआ है। यहां स्वाइन फ्लू के सर्वाधिक मामले सामने आ रहे हैं। यह भी एक अध्ययन का विषय है। *(रा.प., 19.02.18)*

वित्तीय सेवाएं

बैंकों में जमा आठ हजार करोड़ के दावेदार नहीं

देश के अलग-अलग बैंकों में ऐसा काफी पैसा जमा है जिसका कोई दावेदार नहीं है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सभी बैंकों को मिलाकर देखा जाए तो इस रकम का आंकड़ा आठ हजार करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। सरकार द्वारा केवाईसी नियमों में की गई सख्ती की वजह से ऐसे खातों की संख्या बढ़ गई है। खाताधारक की मौत होने पर अब बैंक तब ही किसी को उनके पैसे निकालने देता है जब पैसा मांगने वाला शख्स उस खाताधारक से अपना करीबी रिश्ता स्थापित कर पाए।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अलग-अलग बैंकों के खातों में पड़े 8,864.6 करोड़ रुपए का कोई दावेदार नहीं है। यह आंकड़े दिसंबर 2016 तक के बताए जा रहे हैं। बैंकों में पड़े जिस पैसे का कोई दावेदार नहीं होता वह भी बैंक का घाटा ही करवाता है। दरअसल बैंक उन खातों पर ब्याज देना बंद नहीं कर सकते। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि पिछले दस सालों से जिन खातों का कोई दावेदार सामने नहीं आया है, उनकी लिस्ट तैयार करके सभी बैंक अपनी-अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। अपलोड की गई जानकारी में खाताधारकों के नाम और पता शामिल होंगे। *(रा.प. एवं दै.न., 14.01.18)*

उपभोक्ता फैसले

उपभोक्ता अदालत ने पाया एसबीआई को सेवाओं में कमी का दोषी

अकोला जिले के उपभोक्ता मंच ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को सेवाओं में कमी का दोषी माना है। यह मामला एटीएम से पैसा नहीं निकलने के बावजूद ग्राहक के खाते से पैसा कटने से जुड़ा है। मामले के अनुसार प्रदीप शितरे एसबीआई के एटीएम से 5000 रुपए निकलवाने गए, लेकिन एटीएम से पैसा नहीं निकला और 5000 रुपए उनके खाते में कट गए। उन्होंने एसबीआई की संबंधित शाखा में जाकर बैंक अधिकारियों को इसकी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद वह कई बार बैंक अधिकारियों से मिले लेकिन उन्हें संतोषप्रद जवाब नहीं मिला।

हारकर उन्होंने उपभोक्ता मंच में एसबीआई के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया, जिसमें संबंधित सभी जानकारियां दी गई। मामले की सुनवाई के लिए मंच ने एसबीआई को नियत तिथि पर जवाब प्रस्तुत करने और उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया। लेकिन इसके बावजूद बैंक की ओर से कोई अधिकारी अथवा प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। इस पर मंच ने एक तरफा फैसला देते हुए बैंक को आदेश दिए कि वह खाताधारक प्रदीप शितरे को 5000 रुपए की वह राशि लौटाए, जो उसके खाते से गलत ढंग से काट ली गई थीं। साथ ही मंच ने इसे बैंक की लापरवाही एवं सेवा में कमी मानते हुए 3000 रुपए बतौर मुआवजा व 2000 रुपए परिवाद खर्च देने के भी निर्देश दिए हैं। *(न.नु., 28.01.18)*

खास समाचार

उपभोक्ताओं को नहीं मिल रही राहत

जयपुर स्थित दो जिला उपभोक्ता मंचों का अध्यक्ष के इंतजार में कामकाज ठप हो रखा है। उपभोक्ता मामलात विभाग ने राजधानी में चार जिला उपभोक्ता मंचों का गठन कर रखा है। जिनका क्षेत्राधिकार इलाकों के अनुसार बांटा हुआ है। चार मंचों में लंबित कुल 14 हजार मामलों में से आधे मामले इन दोनों मंचों में रजिस्टर्ड है। रिक्त पदों पर चयन के लिए साक्षात्कार हो चुके हैं लेकिन तीन महीनों से नियुक्ति की प्रक्रिया उपभोक्ता विभाग में अटकी है। ऐसे में उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उपभोक्ता मंच (द्वितीय) में अध्यक्ष का पद नवंबर 2017 के आखरी हफ्ते से रिक्त पड़ा है। इस मंच में उपभोक्ताओं के करीब 4000 मामले लंबित हैं। वहीं उपभोक्ता मंच (तृतीय) में मई 2017 से अध्यक्ष का पद रिक्त है। इस मंच में करीब 3200 मामले लंबित हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार जिला उपभोक्ता मंच में तीन सदस्य होते हैं जिनमें अध्यक्ष और सदस्य के होने पर ही कोरम पूरा माना जाता है।

कोरम के अभाव में मंच किसी भी मामले पर सुनवाई नहीं कर सकता। ऐसे में लंबित मामलों में केवल तारीखें डालने का काम ही हो रहा है। उपभोक्ता आयोग आवेदकों के साक्षात्कार ले चुका है और मामले की फाइल तीन महीने पहले राज्य सरकार के उपभोक्ता मामलात विभाग को भेज चुका है। नियुक्ति का निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर होता है। ऐसे में सरकार की बेरुखि के चलते उपभोक्ताओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। *(दै.भा., 17.02.18)*

खराब क्वालिटी और नकली सामान के लिए उत्पादक दोषी

पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 के स्थान पर नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लोकसभा में पेश किया गया है। इसके बजट सत्र के दौरान पारित होने की संभावना है। पुराने कानून के दायरे में जो विषय बाहर थे, उन्हें नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक-2018 में शामिल किया गया है। नये विधेयक में केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के गठन का भी प्रावधान है। इसका मकसद उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण कर उन्हें ज्यादा सशक्त बनाना है।

यह जानकारी देते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि नए विधेयक के अनुसार निर्माता, सेवा प्रदाता की जवाबदेही सभी उपभोक्ताओं के प्रति होगी ना कि केवल एक उपभोक्ता तक सीमित रहेगी। इसमें विवादों को समय पर निपटाने का भी प्रावधान है। नए विधेयक में अब भारी जुर्माना और जेल की सजा का भी प्रावधान रखा गया है। विधेयक के मुताबिक खराब क्वालिटी और नकली सामान बेचने के लिए उत्पादक को दोषी माना जाएगा।

खाद्य सामग्री में मिलावट को गंभीर मानते हुए मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज के अनुचित व्यापार पर केन्द्र सरकार पूरी नजर रखेगी। विधेयक में इसके लिए खास प्रावधान भी किए गए हैं। उपभोक्ता को भ्रामक विज्ञापनों से मुक्ति मिलेगी। उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले विज्ञापन दाताओं और उसका प्रचार-प्रसार करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान नए विधेयक में शामिल है। *(रा.प., 09.01.18)*

स्त्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, डे.न्यू.: डेलीन्यूज

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259 फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्सः 401 5395, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।